GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
DEPARTMENT OF FERTILIZERS

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION **NO. 352*** TO BE ANSWERED **ON: 05.04.2022**

Domestic production of fertilizers

***352: SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR**:

Will the Minister of **CHEMICALS AND FERTILIZERS** be pleased to state:

(a) the quantum of fertilizers produced by the cooperative and public sector companies of the country during the last four years, company-wise and year-wise;

(b) the quantum of fertilizers required for the farmers annually in the country;

(c) the extent to which the domestic production meets the demand of fertilizers by the farmers during the said period, year-wise;

(d) the details and quantum of fertilizers imported during the said period, year-wise; and

(e) the steps taken by Government to minimise the dependence on import?

ANSWER

MINISTER OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DR. MANSUKH MANDAVIYA)

(a) to (e): A Statement is laid on the Table of the House.

****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) to (e) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 352* TO BE REPLY ON 05.04.2022 REGARDING DOMESTIC PRODUCTION OF FERTILIZERS.

(a): The quantum of fertilizers produced by the Cooperative and Public Sector companies in the country during the last four years company-wise and year-wise are at **Annexure.**

(b) to (d): Requirement/ Demand, Production of Fertilizers and Import during the last four year are given below:-

Year	Requirement/ Demand (Fig. in LMT)			
	Urea	DAP	NPKs	MOP
2017-18	298.00	98.77	98.19	33.90
2018-19	300.04	98.40	97.68	36.81
2019-20	335.26	103.30	104.82	38.12
2020-21	350.64	107.76	108.00	35.51
	Fertilizers Production* (Fig. in LMT)			
2017-18	240.23	46.50	88.14	-
2018-19	238.99	38.99	95.15	-
2019-20	244.55	45.50	93.34	-
2020-21	246.03	37.74	100.54	-
	Import of Fertilizers(Fig. in LMT)			
2017-18	59.75	42.17	4.99	47.36
2018-19	74.81	66.02	5.46	42.14
2019-20	91.23	48.70	7.46	36.70
2020-21	98.28	48.82	13.90	42.27

(*Production of NPKs includes Complexe Fertilizers & Ammonium Sulphate)

(e): The Government had announced New Investment Policy (NIP) – 2012 on 2nd January, 2013 and its amendment on 7th October, 2014 to facilitate fresh investment in the urea sector and to make India self-sufficient in the urea sector. Under NIP – 2012 read with its amendment, Matix Fertilizers and Chemicals Ltd.(Matix), Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd. (CFCL), Ramagundam Fertilizers and Chemicals Ltd.(RFCL) and Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) have set up urea plants of 12.7 LMT per annum capacity each at Panagarh-West Bengal, Gadepan-Rajasthan (Gadepan-III), Ramagundam-Telangana and Gorakhpur-Uttar Pradesh respectively.

In addition to above, revival of 1 closed unit of Fertilizers and Chemicals India Ltd. FCIL namely Sindri and 1 closed unit of Hindustan Fertilizers and Chemicals Ltd. (HFCL) at Barauni by means of setting up of new greenfield urea units of 12.7 LMTPA at each of the locations is also included under the NIP-2012 read with its amendment. For the revival of Talcher unit of FCIL by setting up a new greenfield urea plant of 12.7 LMTPA an exclusive policy has been notified on 28th April 2021.

The Government of India has also notified the New Urea Policy (NUP) – 2015 on 25th May, 2015 for existing 25 gas based urea units with the objective of maximizing indigenous urea production; promoting energy efficiency in urea production; and rationalizing subsidy burden on the Government. The implementation of NUP-2015 has led to additional production from the existing gas based urea units due to which the actual production of urea has increased by 20-25 LMTPA in comparison to the actual production during 2014-15.

Further, Cabinet in its meeting held on 21.05.2015 inter-alia approved setting up of New urea plant of 8.646 LMTPA capacity in the existing premises of BVFCL, which has been notified by the Department of Fertilizes Vide OM Dated 12.6.2015

DoF granted permission to Madhya Bharat Agro product Limited Unit-II, Banda Sagar, MP for production of 1.2 LMT per annum of P&K fertilizers.

Paradeep Phosphates Ltd. has been granted permission to manufacture additional DAP/NPK complex to the tune of 8 LMT per annum utilizing the 2 trains of ZACL Goa Plant.

A new DAP/NPK Plant by RCF with annual capacity of 5 LMT and 5.5 LMT by FACT has been granted permission.

Govt. of India has notified Potash Derived from Molasses (PDM) under the Nutrient Based Subsidy (NBS) scheme which is 100% indigenously produced fertilizer.

****

Annexure

Quantum of fertilizers produced by the Public & Cooperative Sector Companies of the country during the last four years (2017-18 to 2020-21)

Sl. No.	Name of the Company	Plant location	Name of Fertilizers produced	Fertilizer produced (Fig. in 'LMT')			
				2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Public Sector							
1	**Brahmaputra Valley Fertilizers Corporation Ltd. (BVFCL)**	Namrup-II	Urea	0.58	0.58	0.46	0.02
		Namrup-III	Urea	2.12	2.29	1.10	1.299
2	**National Fertilizers Ltd. (NFL)**	Nangal-II	Urea	5.43	5.41	5.75	5.469
		Panipat	Urea	5.60	5.74	5.52	5.827
		Bhatinda	Urea	5.63	5.84	5.63	5.767
		Vijaypur-I	Urea	10.44	10.29	9.84	9.663
		Vijaypur-II	Urea	10.88	11.32	10.53	11.265
3	**Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. (FACT)**	Udyogamandal	Complex & A/S	3.65	2.72	4.31	4.617
		Cochin	Complex	4.87	5.06	6.41	6.46
4	**Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. (RCF)**	Trombay	Urea & Complex	9.19	9.53	8.96	8.77
		Thal	Urea	20.61	19.84	20.22	19.124
5	**Madras Fertilizers Ltd. (MFL)**	Chennai	Urea & Complex	4.81	4.20	4.10	5.344
Cooperative Sector							
6	**Indian Farmers Fertilizer Co-operative Ltd. (IFFCO)**	Kalol	Urea	6.02	6.02	6.02	6.237
		Anola-I	Urea	8.96	11.22	12.20	11.044
		Anola-II	Urea	9.31	11.18	10.87	11.772
		Phulpur-I	Urea	7.26	6.71	7.50	7.057
		Phulpur-II	Urea	9.55	10.48	12.16	10.641
		Kandla	DAP & Complex	20.29	19.23	23.27	22.834
		Paradeep	DAP & Complex	17.24	16.54	19.31	19.883
7	**Krishak Bharati Co-operative Ltd. (KRIBHCO)**	Hazira	Urea	22.54	23.42	23.31	23.234

****

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या **352***

जिसका उत्तर मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022/15 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का घरेलू उत्पादन

352*. श्री के.आर.एन.राजेश कुमार:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों के दौरान देश की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उर्वरकों का कंपनी-वार और वर्ष-वार कितना-कितना उत्पादन किया गया;
(ख) देश में किसानों को उर्वरक की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान किसानों की उर्वरक की मांग घरेलू उत्पादन द्वारा वर्षवार किस हद तक पूरी हो पाती है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान आयातित उर्वरकों का उनकी मात्रा सहित वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) सरकार द्वारा आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री
(डा. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'उर्वरकों का घरेलू उत्पादन' के संबंध में 05.04.2022 को उत्तर दिये जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 352* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): पिछले चार वर्ष के दौरान देश में सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित उर्वरकों की कंपनी-वार और वर्ष-वार मात्रा **अनुलग्नक** में है।

(ख) से (घ): पिछले चार वर्ष के दौरान आवश्यकता/मांग, उर्वरकों का उत्पादन और आयात नीचे दिया गया है:-

वर्ष	आवश्यकता/मांग (आंकड़े एलएमटी में)			
	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी
2017-18	298.00	98.77	98.19	33.90
2018-19	300.04	98.40	97.68	36.81
2019-20	335.26	103.30	104.82	38.12
2020-21	350.64	107.76	108.00	35.51
	उर्वरकों का उत्पादन* (आंकड़े एलएमटी में)			
2017-18	240.23	46.50	88.14	-
2018-19	238.99	38.99	95.15	-
2019-20	244.55	45.50	93.34	-
2020-21	246.03	37.74	100.54	-
	उर्वरकों का आयात (आंकड़े एलएमटी में)			
2017-18	59.75	42.17	4.99	47.36
2018-19	74.81	66.02	5.46	42.14
2019-20	91.23	48.70	7.46	36.70
2020-21	98.28	48.82	13.90	42.27

(*एनपीके के उत्पादन में मिश्रित उर्वरक और अमोनियम सल्फेट शामिल हैं)

(ङ): सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुकर बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधन की घोषणा की थी। अपने संशोधन के साथ पठित एनआईपी - 2012 के तहत, मैटिक्स फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स), चंबल फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल), रामागुंडम फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) और हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) ने क्रमशः पानागढ़-पश्चिम बंगाल, गड़ेपान-राजस्थान (गड़ेपान-III), रामागुंडम-तेलंगाना और गोरखपुर-उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में 12.7 एलएमटी प्रति वर्ष क्षमता के यूरिया संयंत्र स्थापित किये हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की 1 बंद इकाई नामतः सिंदरी और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी स्थित 1 बंद इकाई के प्रत्येक स्थान पर 12.7 एलएमटीपीए की नई ग्रीनफील्ड यूरिया इकाइयों की स्थापना के माध्यम से पुनरुद्धार को भी इसके संशोधन के साथ पठित एनआईपी-2012 के तहत शामिल किया गया है। 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके एफसीआईएल की तलचर इकाई के पुनरुद्धार के लिए 28 अप्रैल 2021 को एक विशेष नीति अधिसूचित की गई है।

भारत सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को इष्टतम करने; यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने; और सरकार पर राजसहायता के बोझ को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 भी अधिसूचित की है । एनयूपी-2015 के कार्यान्वयन से मौजूदा गैस आधारित यूरिया इकाइयों से अतिरिक्त उत्पादन हुआ है जिसके कारण 2014-15 के दौरान हुए वास्तविक उत्पादन की तुलना में यूरिया के वास्तविक उत्पादन में 20-25 एलएमटीपीए की वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने 21.05.2015 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ बीवीएफसीएल के मौजूदा परिसर में 8.646 एलएमटीपीए क्षमता के नए यूरिया संयंत्र की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसे उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 12.6.2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अधिसूचित किया गया है।

उर्वरक विभाग ने मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड यूनिट-II, बांदा सागर, म.प्र. को पीएण्डके उर्वरकों के प्रति वर्ष 1.2 एलएमटी उत्पादन की अनुमति दी।

पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड को जेडएसीएल गोवा प्लांट की 2 ट्रेनों का उपयोग करके प्रति वर्ष 8 एलएमटी अतिरिक्त डीएपी/एनपीके मिश्रित उर्वरक के निर्माण की अनुमति दी गई है।

आरसीएफ द्वारा 5 एलएमटी और एफएसीटी द्वारा 5.5 एलएमटी की वार्षिक क्षमता वाले एक नए डीएपी/एनपीके प्लांट को अनुमति दी गई है।

भारत सरकार ने शीरे से प्राप्त पोटाश(पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, को पोषक तत्व आधारित राजसहायता(एनबीएस)स्कीम के तहत अधिसूचित किया है।

****

अनुलग्नक

पिछले चार वर्ष (2017-18 से 2020-21 तक) के दौरान देश की सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित उर्वरकों की मात्रा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	संयंत्र का स्थान	उत्पादित उर्वरकों का नाम	उत्पादित उर्वरक (आंकड़े 'एलएमटी' में)			
				2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सार्वजनिक क्षेत्र							
1	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	नामरूप-II	यूरिया	0.58	0.58	0.46	0.02
		नामरूप-III	यूरिया	2.12	2.29	1.10	1.299
2	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	नांगल-II	यूरिया	5.43	5.41	5.75	5.469
		पानीपत	यूरिया	5.60	5.74	5.52	5.827
		भटिण्डा	यूरिया	5.63	5.84	5.63	5.767
		विजयपुर-I	यूरिया	10.44	10.29	9.84	9.663
		विजयपुर-II	यूरिया	10.88	11.32	10.53	11.265
3	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी)	उद्योगमंडल	मिश्रित और ए/एस	3.65	2.72	4.31	4.617
		कोचीन	मिश्रित	4.87	5.06	6.41	6.46
4	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	ट्रॉम्बे	यूरिया और मिश्रित	9.19	9.53	8.96	8.77
		थल	यूरिया	20.61	19.84	20.22	19.124
5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)	चेन्नई	यूरिया और मिश्रित	4.81	4.20	4.10	5.344
सहकारी क्षेत्र							
6	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको)	कलोल	यूरिया	6.02	6.02	6.02	6.237
		आंवला-I	यूरिया	8.96	11.22	12.20	11.044
		आंवला-II	यूरिया	9.31	11.18	10.87	11.772
		फूलपुर-I	यूरिया	7.26	6.71	7.50	7.057
		फूलपुर-II	यूरिया	9.55	10.48	12.16	10.641
		कांडला	डीएपी और मिश्रित	20.29	19.23	23.27	22.834
		पारादीप	डीएपी और मिश्रित	17.24	16.54	19.31	19.883
7	कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको)	हजीरा	यूरिया	22.54	23.42	23.31	23.234

****

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rajeshji, put your first supplementary.

SHRI K.R.N RAJESHKUMAR: Hon'ble Deputy Chairman sir, first I thank you Members of this august House and the hon. Ministers because my question is reached,which is at Sl. No.7.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Give your thanks to all your colleagues.

SHRI K.R.N RAJESHKUMAR: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Indian agricultural sector would face the impact arising out of the hostilities between Russia and Ukraine, which are expected to push up the prices and availability of Potash, a key component used in the manufacture of fertilizers. If so, what are the steps intended to be taken by the Government?

श्री भगवंत खूबा : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और पूरे देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि भारत के किसानों को पिछले साल भी उर्वरकों को लेकर बड़ी चिन्ता थी, लेकिन हमने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लेकर भारत के किसानों को सही समय एवं सही दाम पर उर्वरक उपलब्ध करायी है। इस साल भी आने वाली रबी और खरीफ फसलों के लिए भारत सरकार माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सबको आश्वस्त करती है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। महोदय, दुनिया में feedstock की कीमत चार से पांच गुना बढ़ी है, लेकिन भारत सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जिस कीमत पर हम आज दे रहे हैं, उसी कीमत पर किसानों को देंगे।

SHRI K.R.N RAJESHKUMAR: Sir, the Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited (IFFCO) is the largest producer of fertilizers as of now. It was under the Ministry of Chemicals and Fertilizers. That is the relevant Ministry. Logically, IFFCO should work under the Ministry of Chemicals and Fertilizers for better execution. Why has the Ministry decided to transfer this organization to the Ministry of Cooperation?

श्री भगवंत खूबा : माननीय उपसभापति महोदय, IFFCO भी एक को-ऑपरेटिव सेक्टर है और इसीलिए वह उस सेक्टर में काम करता है, किन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत ही हमारे एनबीएस के आधार पर हम production करते हैं और उसे हमारे नियमों के तहत ही हम किसानों को देते हैं।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा : माननीय उपसभापति महोदय, मंत्री जी ने काफी डिटेल में जानकारी दी है। मेरा प्रश्न यह है कि असम में एक fertilizer factory, Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited है, जिसकी यूनिट 1 एवं 2 बंद हो चुकी हैं, यूनिट 3 के लिए हमारे Hon. Finance Minister ने 100 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया था, उस पैकेज का क्या हुआ? चौथी

यूनिट नहीं होने से वह कंपनी बंद हो जाएगी, जबकि नॉर्थ-ईस्ट में फर्टिलाइज़र की आपूर्ति करने वाली यह एकमात्र fertilizer कंपनी है। इसकी यूनिट 1 एवं 2 बंद हो चुकी है। यूनिट 3 के लिए जो 100 करोड़ रुपए दिए, उसका क्या हुआ और यूनिट 4 कब चालू होगी?

श्री भगवंत खूबा : माननीय उपसभापति महोदय, BVFCL की यूनिटों के लिए हमने नेशनल New Urea Policy के अंतर्गत 21 मई, 2015 को permission दी है, ताकि वे फिर से उसे एक बार चालू कर सकें।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the NUP 2015 was brought with the objective of maximising indigenous urea production, promoting energy efficiency in urea production and rationalising subsidy burden on the Government. While rationalising the subsidy burden on the Government, will it not be transferring it on the shoulders of farmers? Already, the farmers are suffering by not getting due and genuine prices for their produce and the input cost has also increased. When the subsidy has been reduced and the burden is on the shoulders of farmers, will you consider the problems faced by the farmers because of the hike in the price of feedstock?

श्री भगवंत खूबा : उपसभापति महोदय, हम New Urea Policy के अंतर्गत maximising indigenous urea production, promoting energy efficiency का मुद्दा लेकर आए थे। हमने इसके अंतर्गत देश के अंदर 25 ऐसे gas-based projects चालू किये हैं। हमने इनको gas-based में convert करके चालू किया है। **...(व्यवधान)...** अगर आप 2014 के बाद से compare करें, तो पाएँगे कि 20 से 25 लाख मीट्रिक टन उत्पादन ज्यादा हुआ है।

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि feedstock की कीमत बढ़ने की वजह से किसानों के ऊपर बोझ बढ़ेगा। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार किसी भी हालत में किसानों के ऊपर बोझ नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि 2021-22 के बजट में इसके तहत BE में 83,548 करोड़ रुपए रखे गये थे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सभी feedstocks की कीमत बढ़ने के बाद भारत सरकार, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने RE के अंदर सब्सिडी को बढ़ा कर 1,62,072 करोड़ रुपए कर दिया, लेकिन किसानों के ऊपर बोझ नहीं बढ़ने दिया। इसके साथ ही इस साल के बजट में पिछले साल के बजट एस्टिमेट से भी ज्यादा पैसा रखा है। माननीया वित्त मंत्री जी ने इसके तहत 1,09,242 करोड़ रुपए दिये हैं, इसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने बजट में इसके तहत पिछले साल से 25,694 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रावधान किया है। अगर इस साल भी कीमत बढ़ती है, तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार किसानों पर किसी हालत में बर्डन नहीं पड़ने देगी, मैं यह विश्वास दिलाता हूँ।

श्री जयप्रकाश निषाद : उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो इस देश के प्रधान मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि जो बहुत सारे उर्वरक कारखाने बंद हो गए थे, उन्होंने उनको पुनः बना कर चालू करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गोरखपुर में जो खाद कारखाना बन कर तैयार है, क्या आप उसको चालू करवा कर किसानों को समय पर भरपूर मात्रा में उर्वरक देने का काम करेंगे?

श्री भगवंत खूबा : उपसभापति महोदय, गोरखपुर खाद कारखाना फरवरी में चालू हो चुका है और अभी उसमें प्रोडक्शन चल रहा है। हमने NIP और NUP के तहत इतने प्लांट्स इसलिए खड़े किए हैं ताकि देश उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बने। आने वाले दिनों में देश में करीब 1,04,000 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा और हमारे किसानों को निश्चित रूप से indigenous production मिलेगा।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 353.